भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 796
07.02.2024 को उत्तर देने के लिए

लंबित अवसंरचना परियोजनाएं

796. कुमारी राम्या हरिदासः

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजमार्ग, रेलवे, बिजली, कोयला आदि सहित विलंबित और रद्द की गई अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या का वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं में देरी और रद्द होने के कारण लागत में हुई वृद्धि का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पांच साल से अधिक समय से विलंबित अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कार्य शुरुआत की मूल तिथि (डी.ओ.सी.) प्रदान नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग(आईपीएमडी) को ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली(ओसीएमएस) पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली चालू केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि की निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है। पिछले पांच वर्षों और वर्त्तमान वर्ष के दौरान विलंबित परियोजनाओं की संख्या का क्षेत्रवार विवरण अनुबंध-क में है।

(ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दिसंबर 2023 माह के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 848 परियोजनाएं ऐसी हैं जो विलंबित हैं और इन विलंबित परियोजनाओं की लागत वृद्धि 26.53% है। इन विलंबित परियोजनाओं की क्षेत्र -वार ब्यौरा उनकी लागत के साथ अनुबंध-ख में है।

(ग) कुल विलंबित 848 परियोजनाओं में से, 70 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें पांच साल से अधिक की देरी हो चुकी है। इन परियोजनाओं का विवरण www.cspm.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) और (ड़) इस मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सभी परियोजनाओं के शुरू होने की मूल/प्रत्याशित तारीख है।

*****

अनुबंध –क

दिनांक 07/02/2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 796 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्षेत्र का नाम	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-23	दिसंबर-23
परमाणु ऊर्जा	4	4	4	4	4	4
नागर विमानन	1	4	11	20	25	21
कोयला	37	41	50	39	48	48
संस्कृति विकास	0	0	1	0	0	0
रक्षा उत्पादन	1	1	1	1	1	0
उच्च शिक्षा विभाग	8	11	14	15	15	14
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	0	1	0	0	0	0
डीपीआईआईटी	0	1	2	1	1	0
उर्वरक	1	4	4	1	0	0
वित्त	1	1	1	0	0	0
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6	14	13	4	2	4
भारी उद्योग	0	1	0	0	0	0
गृह मंत्रालय	3	2	2	5	5	4
खान	0	2	2	6	7	7
पेट्रोलियम	39	50	76	81	86	91
विदयुत	51	40	45	54	54	59
रेलवे	97	144	155	130	115	105
नवीकरणीय ऊर्जा	0	1	0	0	0	0
सड़क परिवहन और राजमार्ग	110	183	135	243	402	450
ग्रामीण विकास	0	3	3	0	0	0
पत्तन और पोत परिवहन	1	0	0	0	1	1
इस्पात	10	7	5	4	5	5
दूरसंचार	3	3	3	3	3	2
शहरी विकास	7	9	10	16	16	16
जल संसाधन	1	3	20	37	31	17
कुल	**381**	**530**	**557**	**664**	**821**	**848**

अनुबंध –ख

दिनांक 07/02/2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 796 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (करोड़ में)	प्रत्याशित लागत (करोड़ में)	लागत वृद्धि(%)
1	परमाणु ऊर्जा	4	67120	87115	29.79
2	नागर विमानन	21	14561.08	16852.73	15.74
3	कोयला	48	65443.21	70051.58	7.04
4	उच्च शिक्षा विभाग	14	6563.79	7105.49	8.25
5	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	3649.55	3746.33	2.65
6	गृह मंत्रालय	4	1826.42	2759.67	51.10
7	खान	7	7333.99	9562.91	30.39
8	पेट्रोलियम	91	301540.29	359258.53	19.14
9	विद्युत	59	170141.19	222987.93	31.06
10	रेलवे	105	313321.26	464231.17	48.16
11	सड़क परिवहन और राजमार्ग	450	314874.76	344196.3	9.31
12	पत्तन और पोत परिवहन	1	5369.18	5362.27	-0.13
13	इस्पात	5	6953.4	7806.37	12.27
14	दूरसंचार	2	709.62	709.62	0.00
15	शहरी विकास	16	164605.84	183614.14	11.55
16	जल संसाधन	17	15534.56	61431.31	295.45
	कुल	**848**	**1459548.14**	**1846791.35**	**26.53**